

दि कर्मिक पोस्ट

Global
School Of
Excellence,
Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 48

(प्रति बुधवार), इन्दौर, 19 जुलाई 2023 से 25 जुलाई 2023

पेज : 8

कीमत : 3 रुपये

जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सक्षम हैं हमारे पारंपरिक घर



नई दिल्ली।

लघु न दीजिए डारि 2011 के आंकड़े बताते हैं कि पहले ओडिशा व पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से पारंपरिक निर्माण सामग्री का ही उपयोग किया जाता था लेकिन 2022 में एक शोध से पता चला कि अब निर्माण सामग्री में कंक्रीट, लोहे आदि के इस्तेमाल का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है 2011 के आंकड़े बताते हैं कि पहले ओडिशा व पश्चिम बंगाल में प्रमुख रूप से पारंपरिक निर्माण सामग्री का ही उपयोग किया जाता था लेकिन 2022 में एक शोध से पता चला कि अब निर्माण सामग्री में कंक्रीट, लोहे आदि के इस्तेमाल का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है सभ्यता की शुरुआत से ही आश्रय मनुष्य की बुनियादी जरूरतों में से एक रहा है। हमारा घर हमें खराब मौसम, कीड़े-मकोड़ों और अन्य खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि अपने स्वयं का एक घर होने की इच्छा के पीछे का एकमात्र कारण सुरक्षा ही नहीं है, घर होने से हमारे अंदर पहचान, स्वामित्व और अपनेपन की भावना आती है। ग्रामीण क्षेत्र वैश्वीकरण और औद्योगिकीकरण की तकनीकी प्रगति से कम प्रभावित हुए हैं।

इसी कारण से गांवों के घर अपने निवासियों की सामाजिक-सांस्कृतिक व आर्थिक स्थिति को प्रतिबिंबित करते हैं। आधुनिक शहरी क्षेत्रों के हालात इसके ठीक विपरीत हैं, जहां आवासों का निर्माण जलवायु प्रतिक्रिया और सामाजिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों पर आधारित होने के बजाय बाजार की ताकतों व उद्योगों द्वारा संचालित होता है। यही कारण है कि ग्रामीण घर अब भी अपने संदर्भ और पर्यावरण से बहुत अधिक गहराई से जुड़े प्रतीत होते हैं, जबकि आधुनिक शहरों की सूरत अपेक्षाकृत नीरस हो गई है। पारंपरिक निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री अक्सर स्थानीय वनस्पति से प्राप्त होती है। स्थानीय निवासी और राजमिस्त्री भले ही औपचारिक रूप से शिक्षित न हों लेकिन वे स्थानीय जलवायु परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए किसी क्षेत्र विशेष में विकसित होने वाली निर्माण तकनीकें वर्षों के प्रयोगों और

समायोजन का परिणाम होती हैं। ये निर्माण ऐसी भौतिक रचनाओं और रूपों को अपनाते हैं जो प्राकृतिक चुनौतियों के प्रति सर्वाधिक अनुकूल हों और उनके कार्यान्वयन में लचीलापन हो। जैसे, भीषण गर्मी वाले क्षेत्रों में सघन पदार्थों से बनी मोटी दीवारें होती हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में घरों की दीवारें मिट्टी या पत्थर की होती हैं। ठंडी जलवायु में दीवारों को पुआल व लकड़ी से बनाया जाता है जिससे वे इन्सुलेशन का काम करती हैं। इसी तरह, ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में जहां भारी वर्षा होती है, वहां छतें खड़ी और ढलान वाली होती हैं। पुरी के पास के क्षेत्र जहां उच्च वेग वाली हवाएं चलती हैं, वहां घरों को ऐसे बनाया जाता है जिससे वे वायु को कम से कम प्रतिरोध प्रदान करें।

निर्माण प्रौद्योगिकियों में परिवर्तन- 2022 में, दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा

यह विश्लेषण किया कि कैसे भारत में ग्रामीण समुदाय आवास बनाने के लिए स्थानीय सामग्री और निर्माण तकनीकों का उपयोग करते हैं। इस शोध के दौरान निर्माण तकनीक में उल्लेखनीय बदलाव का पता चलता है। 2011 के आंकड़े बताते हैं कि पहले (भारत की पिछली जनगणना के अनुसार) ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से पारंपरिक निर्माण सामग्री जैसे घास, छप्पर, बांस, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि, 2022 में जमीनी जांच से पता चला है कि नए निर्माणों में लाल ईंटें, कंक्रीट, लोहा, अभ्रक और धातु की चादरों के इस्तेमाल में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बदलाव की अपनी वजहें हैं। लाल ईंटों से बनी दीवारें टिकाऊ होती हैं जबकि धातु की चादरों को छप्पर की छतों की तुलना में बहुत कम रखरखाव की आवश्यकता होती

है। कंक्रीट बहुपयोगी होता है और त्वरित निर्माण में मदद करता है। हालांकि, इन सामग्रियों का उपयोग दीर्घकालिक चुनौतियों का कारण बन सकता है। निर्माण सामग्री के विकास के इतिहास में, यह हालिया बदलाव अचानक आया है। यह ठीक उसी तरह है जैसे पाषाण युग के एक शिकारी-संग्रहकर्ता को कांस्य युग का धातु से बना कृषि उपकरण सौंप दिया जाए। यह उपकरण चमकदार होने के साथ-साथ पत्थर की तुलना में अधिक टिकाऊ तो है लेकिन शिकारी के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है और उसकी आवश्यकताओं पर खरा नहीं उतरता है। उसी तरह, आधुनिक प्रौद्योगिकियां कई पहलुओं में पारंपरिक तकनीकों के लाभों से मेल नहीं खाती। ईंट, सीमेंट, धातु और एस्बेस्टस शीट गांवों से दूर कारखानों में निर्मित होते हैं। उनके परिवहन की अपनी प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप अर्ध या

अकुशल ग्रामीण कार्यबल की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्थानीय रोजगार सृजन में बाधा आती है। थर्मल कम्फर्ट के मामले में भी वे पारंपरिक सामग्रियों से कमतर हैं। इसके फलस्वरूप लोगों को ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरणों का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जिससे उनकी बिजली का बिल बढ़ जाता है। अपने जीवनचक्र के अंत में ये आधुनिक सामग्रियां कूड़ा-करकट में बदल जाती हैं, जिससे निपटना छोटे गांवों के लिए तो मुश्किल है ही, बड़े शहरों के लिए भी यह टेढ़ी खीर साबित होती है। इस निर्माण में स्थानीय समुदाय, विशेषकर महिलाओं की भूमिका को सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। सीएसई के शोध से पता चलता है कि देश के कई ग्रामीण हिस्सों में महिलाएं पारंपरिक ज्ञान और कौशल की अग्रदूत हैं।

सोलर पैनल कैसे आने वाले वक्त में पर्यावरण के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकते हैं?

नई दिल्ली। कार्बन उत्सर्जन कम करने की लड़ाई में सोलर पैनल को दुनियाभर में बेहद अहम हथियार के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि इसकी उम्र महज 25 साल है। जानकारों का कहना है कि अरबों पैनलों को आखिरकार बदलने और इससे पैदा हुए इलेक्ट्रॉनिक कचरे को निपटाने की ज़रूरत जल्द ही बड़ी समस्या बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में सोलर पैनल रीसाइक्लिंग मामलों के एक्सपर्ट डॉ. रॉग डेंग का कहना है, पूरी दुनिया में अब तक एक टेरावॉट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। उनके मुताबिक, सामान्य सोलर पैनल की क्षमता 400 वॉट की होती है। अगर हम छतों और सोलर फ़ार्मों में लगे सोलर पैनलों को शामिल करें तो इनकी संख्या ढाई अरब होगी। ब्रिटिश सरकार के अनुसार, ब्रिटेन में दसियों लाख सोलर पैनल लगाए गए हैं। लेकिन इन्हें हटाने या रीसाइकिल करने की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। दुनियाभर के एक्सपर्ट सरकारों से गुहार लगा रहे हैं कि वो इसे लेकर कोई ठोस नीति बनाएं। उनका कहना है कि वैश्विक स्तर पर इसके बड़ी पर्यावरण आपदा बनने का खतरा मंडरा रहा है। इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (आईआरईएनए) की डिप्टी डायरेक्टर यूटे कोलियर का कहना है, अगर हम इसके रीसाइकिलिंग प्लांट की ओर नहीं बढ़ें तो 2050 तक सोलर पैनलों के कचरे का पहाड़ खड़ा होने जा रहा है। वो



कहती हैं, हम सतत ऊर्जा की तरफ़ बढ़ रहे हैं अधिक से अधिक सोलर पैनल बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है लेकिन हम इससे निपटेंगे कैसे? इसी साल जून के आखिर में फ़्रांस में सोलर पैनल को पूरी तरह रीसाइकिल करने वाली दुनिया की पहली फ़ैक्ट्री काम करना शुरू कर देगी। इस फ़ैक्ट्री के लगने के साथ ही इस दिशा में काम करने वालों की उम्मीद जगी है। इस रीसाइकिलिंग कंपनी का नाम है आरओएसआई (रोसी) जो फ़्रांस के ग्रेनोबल में अपना प्लांट लगा रही है। कंपनी को उम्मीद है वो सोलर पैनल के 99 फ़ीसदी हिस्से को फिर से इस्तेमाल लायक बनाने में सफल रहेगी। यह फ़ैक्ट्री, सोलर पैनल के कांच और एल्युमीनियम फ़्रेम के

साथ-साथ उसमें लगे कीमती धातुओं- चांदी और तांबे को अलग करने का काम करेगी, जिन्हें अलग-अलग करना सबसे मुश्किल काम है। इन दुर्लभ धातुओं को रीसाइकिल करने के बाद अधिक क्षमता वाले सोलर पैनल में फिर से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। रीसाइकिलिंग के परम्परागत तरीकों से एल्युमीनियम और कांच को अलग किया जा सकता है लेकिन रोसी का दावा है कि इससे मिला कांच अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता का होता है। इस तरह से निकाले गए कांच का इस्तेमाल टाइल्स बनाने जैसे कामों में किया जा सकता है या फिर ये कोलतार बनाने के लिए अन्य चीजों के साथ मिलाने के काम भी आ सकता है। लेकिन इनका इस्तेमाल उच्च क्षमता वाले हाईग्रेड सोलर पैनल में नहीं किया जा सकता। रोसी फ़ैक्ट्री ऐसे समय शुरू की जा

रही है जब सोलर पैनल लगाने की धूम मची हुई है। साल 2021 तक दुनिया भर में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में 22ब की बढ़ोत्तरी हुई है। अकेले ब्रिटेन में ही हर महीने 13,000 सोलर पैनल लगाए जाते हैं, जो अधिकांश लोगों के घरों के छतों पर लगाए जाते हैं। अधिकांश मामलों में अपनी अनुमानित उम्र पूरा होने से पहले ही सोलर पैनल बहुत उपयोगी नहीं रह जाते। लगातार तकनीक उन्नत हो रही है, इसका मतलब है कि ऐसे अपडेटेड पैनल आ जाएंगे जो 10-15 साल पुराने सोलर पैनलों से बदलने में सस्ते पड़ेंगे। कोलियर कहती हैं कि अगर सोलर पैनल की धूम की गति यही रही तो खराब हो चुके सोलर पैनल का कचरा और भी बढ़ा हो सकता है। उनके मुताबिक, हम समझते हैं कि 2030 तक हमारे पास 40 लाख टन सोलर कचरा होगा, जिसका

फिर भी निपटारा किया जा सकता है, लेकिन 2050 तक वैश्विक स्तर पर 20 करोड़ टन कचरा हो सकता है। पहली पीढ़ी के सोलर पैनल अब जाकर बेकार होना शुरू हुए हैं। चूंकि अब बहुत सारे सोलर पैनल रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे हैं, इसलिए एक्सपर्ट के अनुसार, इस मामले में बहुत जल्द कार्रवाई करने की ज़रूरत है। निकोलस डीफ्रेनी का कहना है कि सोलर पैनल रीसाइक्लिंग में फ़्रांस यूरोप में सबसे आगे है। उनका संगठन सोरेन, रोसी और अन्य फ़र्मों का पार्टनर है और पूरे फ़्रांस में सोलर पैनलों को रिटायर करने की निगरानी का काम भी करता है। निकोलस के अनुसार, जो सबसे बड़ा प्लांट जो हमने रिटायर किया, उसमें तीन महीने लगे। सोरेन में उनकी टीम रीसाइक्लिंग की अलग-अलग तरकीबें आजमा रही हैं। ग्रेनोबल के रोसी हाईटेक प्लांट में सोलर पैनलों के अंदर लगे बहुमूल्य धातुओं जैसे चांदी, सिलिकॉन और तांबे को निकालने का काम सबसे कठिन है। ये अन्य कंपोनेंट में इस तरह और इतनी कम मात्रा में लगे होते हैं कि इन्हें अलग करना अभी तक आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित नहीं हो पाया है। निकोलस कहते हैं कि चूंकि ये धातुएं इतनी बहुमूल्य हैं कि इन्हें प्रभावी तरीके से निकालने का तरीका अगर ढूंढ लिया जाए तो ये 'गेमचेंजर' हो सकता है। उनके मुताबिक, सोलर पैनल में 60ब कीमती चीजें उसके सिर्फ 3ब वज़न में मौजूद होती हैं।

इंदौर स्काडा सिस्टम से रोज बचा रहा दो करोड़ लीटर पेयजल, भोपाल में प्रतिदिन 10 करोड़ लीटर पानी की हो रही बर्बादी



भोपाल शहर में पिछले 10 वर्षों में 500 करोड़ रुपये की राशि शहर के वाटर सप्लाई नेटवर्क पर खर्च कर दी गई है। इसके बाद भी एक लीकेज के बाद शहर की आबादी पानी के लिए तरस जाती है। लीकेज के दौरान लाखों गैलन पानी भी व्यर्थ बह जाता है। जबकि इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए शहर में पांच वर्ष पूर्व शहर के वाटर सप्लाई नेटवर्क पर स्काडा सिस्टम लगाने की योजना बनी थी। वैसे तो इस सिस्टम को आठ माह में लगाया जाना था, लेकिन यह अब भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो सका है। जबकि इंदौर पूरे वाटर सप्लाई नेटवर्क पर यह सिस्टम लागू कर एक-एक फिट लाइन की मॉनिटरिंग कर रहा है, जिससे रोजाना दो करोड़ लीटर व्यर्थ बहने वाले पानी को बचाया जा रहा है, जबकि भोपाल में अब भी रोजाना 10 करोड़ लीटर पानी लीकेज के कारण बर्बाद हो जाता है।

शहर में पूरी तरह स्काडा सिस्टम लगने से शहर की चारों जल प्रदाय परियोजना को पूरी तरह से जोड़ा जा सकेगा। जिसके कारण किसी क्षेत्र में पानी की सप्लाई न होने से दूसरे जल स्रोत के पानी को लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। इससे शहर में लीकेज के दौरान होने वाली पानी की समस्या पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकेगा। वर्तमान में इस सिस्टम की सहायता से कोलार परियोजना को केरवा परियोजना के साथ जोड़ा गया है। ऐसे में केरवा की सप्लाई बाधित होने पर कोलार की सप्लाई की जाती है। वहीं कोलार सप्लाई बाधित होने पर केरवा के पानी की सप्लाई की जाती है। स्काडा यानी सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्जिजिशन सिस्टम एक ऑटोमेशन सिस्टम है। यह किसी भी तरह के सप्लाई नेटवर्क की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करता है। इंदौर और भोपाल सहित कई बड़े शहरों में पानी सप्लाई की मॉनिटरिंग करने के लिए इस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इस सिस्टम की सहायता से पानी की पाइप लाइन में लीकेज होने पर या किसी पानी की सप्लाई किसी भी कारण से रुकने पर इसकी जानकारी ऑपरेटर को मिल जाती है। पानी का दबाव कम होने की सटीक जानकारी भी स्काडा के माध्यम से मिलती है।

हरियाणा में बाढ़ से जीवित हुई कई नदियां, किसानों ने कहा- प्रबंधन होता तो नुकसान नहीं होता

अंबाला हरियाणा के अंबाला जिले के सेगता गांव के किसान बलजीत सिंह ने अपना दायां हाथ उठाकर करीब 500 मीटर दूर सफेदों के झूंड की और इशारा कर बताया कि टांगरी नदी का बांध वहां से टूट गया है और गांव में उसी के पानी से बाढ़ आई हुई है।

जिस सड़क पर खड़े हो बलजीत सिंह टांगरी नदी दिखा रहे थे, वह भी पानी से कट चुकी थी और टांगरी नदी की तरफ से लगातार बह रहे पानी के कारण खेत और नदी में अंतर कर पाना मुश्किल था। खेतों से सड़क करीब चार फीट ऊंचाई पर थी, और पानी के तेज बहाव ने उसे कई जगह से काट दिया था। बलजीत सिंह ने बताया, यह सारा पानी आगे कई गांव से होता हुआ घग्घर में जाकर गिरेगा। टांगरी नदी भी जाकर घग्घर में गिरेगी। हालांकि टांगरी कई जगह से टूटी हुई है। बलजीत टांगरी नदी का यह रूप 10-12 साल के अंतराल के बाद देख रहे हैं। वह कहते हैं, सरकार इन छोटी-छोटी नदियों को भुलाए बैठी है और इनको गंदे नालों में तब्दील कर दिया है, जबकि अगर इनके तटबंध और साफ सफाई का ध्यान रखे तो कोई दिक्कत नहीं आए। टांगरी नदी से अंबाला के करीब 50 गांव प्रभावित हैं, लेकिन यह नदी जिस बड़ी नदी घग्घर में जाकर मिलती है, उसकी मार हरियाणा के 6, पंजाब के 4 और राजस्थान के 2 जिलों तक पड़ी



है। घग्घर नदी और उसकी कई सहायक नदियां हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की शिवालिक तलहटी से निकलती हैं। इन सहायक नदियों में कौशल्या नदी, टांगरी, मारकंडा, बेघना और सुखना नदी मुख्य हैं जो घग्घर में समाहित हो जाती हैं। पंजाब विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर विश्वबन्धु बताते हैं, शिवालिक की तलहटी, जिसमें अधिकांश हिस्सा मुख्य नदी और इन सहायक नदियों का जलग्रहण क्षेत्र था, उसमें बढ़ती आवासीय बसावट, औद्योगिक इकाइयों और सीवेज से खतरे का सामना कर रही हैं। इनकी धाराओं और तटीय इलाकों को इतनी बुरी तरह से कब्जा लिया गया है कि नक्शे पर दिखने वाली नदी को मैदान पर ढूँढना मुश्किल हो जाएगा। उनके मुताबिक जलग्रहण क्षेत्र के क्षरण ने इन बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों में तब्दील कर दिया है। पंचकुला में बने कौशल्या डैम के आसपास भारी बसावट है। घग्घर के तटीय क्षेत्र को बहुत छोटा बना दिया गया है और आगे मैदान में कहीं-कहीं घग्घर की धारा तक के निशान मिटा दिए गए हैं। इस मॉनसून में

शिवालिक की पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के कारण घग्घर और उसकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) आ गई। इससे पंचकुला, डेराबस्सी, अंबाला, शाहबाद जैसे कई शहरों में गलियों में नहरों की तरह पानी बह रहा है। कॉलोनियां नदियों के तटों और जलग्रहण क्षेत्रों में ही बसी हुई हैं। टांगरी नदी के बाद हम अंबाला और कुरुक्षेत्र के बीच जीटीरोड पर मारकंडा नदी के किनारे बसे शहर शाहबाद गए। शहर के किनारे पर बह रही मारकंडा नदी करीब आधा किलोमीटर चौड़ी दिख रही थी। सामने देखने पर यह नहीं समझ आ रहा था कि नदी की धारा कहां है और खेत कहां है। मारकंडा नदी भी टांगरी नदी की तरह ही कई जगह से टूट गई है। कृषि विशेषज्ञ रमनदीप मान ने बताया, टांगरी और मारकंडा दोनों नदियों को तो मरा हुआ मान लिया गया था। लोगों ने इनकी धारा तक को मिटा दिया है। अंबाला कैट में

कई रिहायशी कलोनियां टांगरी के बिल्कुल तट को घेरकर बनी हुई हैं। टांगरी और मारकंडा जिस मुख्य नदी घग्घर में जाकर मिलती हैं, उसके हाल भी उन दोनों के जैसे ही है। रमनदीप बताते हैं कि पंचकुला, डेराबस्सी और आसपास की रिहायशी कलोनियां घग्घर के किनारे बसी हैं। जैसे ही घग्घर हरियाणा के देहाती इलाकों में घुसती है। वहां भी अतिक्रमण है। घग्घर नाला मात्र रह गई है। अब उसका विकराल रूप आपको डरा रहा है। अंबाला जिला खत्म होते-होते घग्घर में टांगरी, बेघना और मारकंडा नदी मिलती हैं। रमनदीप कहते हैं कि घग्घर ने अंबाला जिले से निकलने के बाद पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर के आसपास के गांव में बहुत ज्यादा नुकसान किया है। वहां हरियाणा और पंजाब दोनों सूबों के गांव में पानी घूम रहा है। संगरूर से हिसार होते हुए दिल्ली जाने वाला नेशनल हाइवे भी टूट चुका है। घग्घर का पानी इस हाइवे के ऊपर से गया है। यह हाइवे पंजाब के मालवा इलाके को दिल्ली से जोड़ता है। घग्घर में खनौरी बॉर्डर पर 15 जुलाई को 754.2 फीट पानी चल रहा था, जोकि खतरे के निशान से 6 फुट ऊपर है। घग्घर नदी पर हरियाणा

के गुहला चीका पर बने हेड के गेज डूबे हुए हैं, जिसके कारण आसपास के करीब 45 गांव जलमग्न हैं। घग्घर के पानी की वजह से हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा और पंजाब के मोहाली, पटियाला, संगरूर और मानसा जिले के इलाकों में बाढ़ आई है। घग्घर का डर राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में पसरा हुआ है और प्रशासन ने वहां हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वही दूसरी तरफ हरियाणा-उत्तरप्रदेश बॉर्डर पर बहने वाली यमुना नदी के तटबंध टूटने के कारण हरियाणा के यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल और फरीदाबाद जिले के इलाकों में बाढ़ आई है। हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार मनोज ठाकुर कहते हैं कि घग्घर और इसकी सहायक नदियों को अतिक्रमण ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। वही यमुना नदी को अवैज्ञानिक और अवैध माइनिंग कर नुकसान पहुंचाया गया है। पिछले 2 साल से नदियों के तटबंध बांधे नहीं गए हैं और नदियों की धारा के बीच माइनिंग और अतिक्रमण के कारण नदियों ने संतुलन खो दिया है। हरियाणा में 1 जून से 15 जुलाई के बीच 214.9 मिमी बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 123.3 मिमी है। अब तक राज्य के 1385 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और 26 लोगों की मौत हो चुकी है। तीन लोग गायब बताए गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 1,60,645 हेक्टेयर में लगी फसल बाढ़ से प्रभावित है।

एयर क्वालिटी ट्रेकर- अंकलेश्वर-झांसी सहित 100 शहरों में संतोषजनक रहा वायु गुणवत्ता का स्तर, हनुमानगढ़ में दर्ज किया गया जानलेवा

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 18 जुलाई 2023 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 219 में से 88 शहरों में हवा %बेहतर% रही, जबकि 100 शहरों की श्रेणी संतोषजनक रही, 28 शहरों में वायु गुणवत्ता मध्यम रही, जबकि बारां (239) और श्रीगंगानगर (218) में वायु गुणवत्ता का स्तर %खराब% रहा। वहीं हनुमानगढ़ (325) में वायु गुणवत्ता का स्तर जानलेवा रहा। यदि दिल्ली की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 113 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद में इंडेक्स 119, गाजियाबाद में 99, गुरुग्राम में 110, नोएडा में 94, ग्रेटर नोएडा में 121 पर पहुंच गया है। देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 80 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के %संतोषजनक% स्तर को दर्शाता है। जबकि लखनऊ में यह इंडेक्स 65, चेन्नई में 96, चंडीगढ़ में 60, हैदराबाद में 49, जयपुर में 167 और पटना में 74 दर्ज किया गया।



पांच साल में बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले 13.5 करोड़ लोग-नीति आयोग

नई दिल्ली। 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी संबंधी अनुमान प्रदान करने वाली इस रिपोर्ट के मुताबिक, बहुआयामी गरीबी के अनुपात में सबसे अधिक कमी उत्तर प्रदेश में आई है। दूसरे नंबर पर बिहार, उसके बाद मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में हुई है। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए जो कि गरीबी की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बहुआयामी गरीबी की संख्या जो वर्ष 2015-16 में 24.85 प्रतिशत थी, गिरकर वर्ष 2019-2021 में 14.96 प्रतिशत हो गई, जिसमें 9.89 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट आई। इस अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65 प्रतिशत से गिरकर 5.27 प्रतिशत हो गई, इसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी तीव्रतम गति से 32.59 प्रतिशत से घटकर 19.28 प्रतिशत हो गई है। रिपोर्ट को नवंबर

2021 में लॉन्च किए गए भारत के एमपीआई की बेसलाइन रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। जिसे वैश्विक कार्य पद्धति के अनुरूप तैयार किया गया है। राष्ट्रीय एमपीआई में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के तीन समान रूप से भारित आयामों में एक साथ अभावों को मापा जाता है। जो सतत विकास लक्ष्य-12 में दिए गए संकेतकों द्वारा दर्शाया गया है। इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, परिसंपत्ति और बैंक खाते शामिल हैं, सभी में उल्लेखनीय सुधार देखे गए हैं। एमपीआई मूल्य 0.117 से लगभग आधा होकर 0.066 हो गया है और वर्ष 2015-16 से 2019-21 के

बीच गरीबी की तीव्रता 47 प्रतिशत से घटकर 44 प्रतिशत हो गई है। दावा किया गया है कि इसके फलस्वरूप भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 (बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा कम करने का लक्ष्य) को हासिल करने के पथ पर अग्रसर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वच्छता, पोषण, रसोई गैस, वित्तीय समावेशन, पेयजल और बिजली तक पहुंच में सुधार पर सरकार के समर्पित फोकस से इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के सभी 12 मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नीति आयोग की ओर से प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य में अभावों को कम करने

में योगदान प्रदान किया है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) जैसी पहलों ने देशभर में स्वच्छता संबंधी सुधार किया है। स्वच्छता अभावों में इन प्रयासों के प्रभाव के परिणामस्वरूप तेजी से और स्पष्ट रूप से 21.8 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के माध्यम से सब्सिडी वाले रसोई गैस के कारण रसोई गैस की कमी में 14.6 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ है। सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) और समग्र शिक्षा जैसी पहलों ने भी बहुआयामी गरीबी को कम करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। विशेष रूप से बिजली के लिए अत्यन्त कम अभाव दर, बैंक खातों तक पहुंच तथा पेयजल सुविधा के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त करना

नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने तथा सभी के लिए एक उज्वल भविष्य बनाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपस में अत्यधिक जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों और पहलों के लगातार कार्यान्वयन से कई संकेतकों में होने वाले अभावों में उल्लेखनीय कमी आई है। विज्ञप्ति के मुताबिक नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण [एनएफएचएस-5 (2019-21)] के आधार पर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) का यह दूसरा संस्करण दोनों सर्वेक्षणों, एनएफएचएस-4 (2015-16) और एनएफएचएस-5 (2019-21) के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति को दर्शाता है।

वाक फॉर जी-20 का शुभारंभ-पर्यावरण मित्र अभियान के तहत युवाओं ने ली 'पर्यावरण मित्र चैलेंज' की शपथ

इंदौर मेयर पुष्पमित्र भार्गव व निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह ने रविवार सुबह शहर में आयोजित जी-20 बैठक के प्रमोशन के लिए 56 दुकान से वाक फॉर जी-20 को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया।

इस अवसर पर मेयर ने कहा कि जी-20 सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि इंदौर आएंगे। 'अतिथि देवो भव' के आधार पर हमें उनका स्वागत करना है इसलिए यह आयोजन किया गया है। दुनियाभर के देश के लोग इंदौर में बैठकर लेबर और एम्प्लॉयमेंट पर चर्चा करेंगे जिसका लाभ इंदौर को जरूर मिलेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि निगम द्वारा शहर में हरियाली बढ़ाने के लिए 17 जुलाई को सोमवती अमावस्या के अवसर पर शहर में पौधारोपण का महाअभियान



शुरू किया है जिसमें सभी लोग शामिल हों। निगम कमिश्नर ने कहा कि वाक फॉर जी-20 का उद्देश्य नागरिकों को जी-20 के बारे में जानकारी प्राप्त हो। हमारे लिए गर्व की बात है कि इतना बड़ा आयोजन इंदौर में हो रहा है। इसमें सभी की सहभागिता से यह आयोजन सफल होगा। इस अवसर पर शहर के विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के साथ ही 500 से अधिक युवाओं द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर वाक फॉर जी-20 में शामिल हुए। 56 दुकान से शुरू हुई वाक फॉर जी-20 जंजीरवाला चौराहा, रसकोर्स रोड, लैंटर्न चौराहा होते हुए फिर 56 दुकान पर समाप्त हुई। इस दौरान युवाओं ने जी-20 बैठक को लेकर नागरिकों को स्वच्छता एवं जागरूकता का संदेश दिया। इसके बाद युवाओं को 'पर्यावरण मित्र अभियान' के तहत 17 जुलाई को आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही एक-एक पौधा लगाने एवं 'पर्यावरण मित्र चैलेंज' की शपथ दिलाई गई।